श्री ओम प्रकाश त्यागी : जिन किसानों ने गन्ना दे दिया है उसके मूल्य किसानों को सीजन के अन्त तक वसूल हो जाएंगे और पिछला जो 20–22 करोड़ का बकाया है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : गन्ने के दाम की अदायगी गन्ना सीजन खत्म होने के तुरन्त बाद कराई जाएंगी और मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो थोड़े बहुत दो एक परसेंट कमी रह जाती रही है पिछले सालों में उससे अधिक इस साल नहीं होने पाएगी ।

SHRI S. R. DAMANI: In view of the fact that the hon. Minister had stated that there would be heavy carry forward stock of sugar and bank money will be locked up in that to a great extent, and secondly in view of the uncertainty whether the sugar producers would be in a position to purchase sugarcane sufficiently because their money is locked up in the loans and sugar stocks, may I know whether the hon. Minister is considering the creation of a buffer stock in sugar on government account? May I also know whether the government will consider allowing some export of sugar so that the country can maintain some supply to its customers outside?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is a hypothetical question, we cannot give a definite reply as to what will happen next year. We shall deal with the situation as it arises; we shall ensure that the factories work.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Next question. You can discuss this in the debate on the Demands for Grants of the Agriculture Ministry.

Solution of Chronically Drought Affected Areas in M.P.

*556. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing:—

(a) whether Government are satisfied with the scheme framed to resolve the problems of chronically drought affected areas in Madhya Pradesh during the Fifth Plan Period;

(b) if not, the details regarding the new schemes that have been framed recently for Sixth Five Year Plan; and

(c) the details regarding the progress made during the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Drought Prone Areas Programme in Madhya Pradesh covers the following 42 blocks in 6 districts:

Districts	Name of the Blocks
1. Jhabua .	Alirajpur, Bhabra, Jhabus, Johat, Kathiwara, Maghnagar, Petlawad, Rama, Ranapur, Sendhwa, Thandla, Uadigarh.
2. Dhar . .	Kukshi, Bagh, Dahi, Nisarpur, Gandhwani, Manwar, Bakaner, Umarband.
3. Betul . .	Amla, Prabhatpatan Ghoda-dongri, Multai. Bhimpur, Chicholi, Shahpur, Betul.
4. Sidhi . .	Majhauli, Kushmi, Deosar, Waidhan, Sidhi, Rampur, Chitrangi, Sihawal.
5. Khargone .	Thikari, Rajpur, Barwani, Pati.
6. Shahdol .	Beohari, Jaisinghnagar.

The objectives of the programme are:

(i) Reducing the severity of the impact of drought;

(ii) Stabilising the income of the people, particularly the weaker sections of the society; and

(iii) Restoration of ecological balance.

The programme outlay for the original Fifth Plan period for Madhya Pradesh was envisaged as Rs. 24·80 crores. In addition to this, an outlay of Rs. 212·79 lakhs as outright central grant was provided for Medium Irrigation Schemes. The outlay for 1977-78 is Rs. 6·42 crores. For 1978-79, the tentative outlay is

Rs. 11·31 crores. During the Fifth Plan upto end of January 1978, an expenditure of Rs. 12·88 crores has been incurred.

The physical achievements during the Fifth Plan upto December, 1977 are as follows:

(i) Irrigation potential created: 18,675 hectares;

(ii) Are abrought under soil conservation measures: 19,053 hectares;

(iii) Forest plantations: 4884 hectares;

(iv) Pasture Development: 2,237 hectares;

(v) Farm Forestry: 567 hectares;

(vi) Number of crop demontrations: 253;

(vii) Number of milch animals distributed: 304; and

(viii) Number of Mandays of employment created: 120 lakhs.

Thus, the implementation of the programme, on the whole, has been satisfactory.

In pursuance of the objective of providing full employment through productive programmes, during the next plan there will be greater emphasis on quick employment generating individual beneficiary schemes to benefit the weaker sections of the society. Intensive development of 25 blocks out of 42 blocks covered under D.P.A.P. in Madhya Pradesh is expected to be taken up during 1978-79. Outlay for each block for this purpose will be Rs. 5·00 lakhs out of which the Government of India will provide Rs. 4·00 lakhs and the State Government Rs. 1·00 lakh. These outlays will be utilised for intensifying such selected programmes suitable for the particular area which can generate additional employment and raise the income level of identified target groups consisting of small and marginal farmers, share croppers, agricultural labourers, rural artisans and persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes, etc.

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सूखाग्रस्त क्षेत्र की समस्या अकेले मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की समस्या है । प्रति वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है और चाहे केन्द्रीय सकार हो या प्रांतीय सरकारें हों बहुत बड़ी राशि राहत कार्य के लिये खर्च करती है । मैं मंत्री महोदय से पूछुंगा कि क्या इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार यह उचित समझती है कि इस समस्या को हल करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विचार करें ?

श्री भानु प्रताप सिंह : राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया गया है उसी का परिणाम है कि यह ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट स्कीम हम चला रहे हैं और उस पर काफ़ी धनराशि व्यय कर रहे हैं । इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता कि हम नये सिरे से राष्ट्रीय प्रश्न समझ कर विचार करें ।

श्री सुखेन्द्र सिंह : मंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर रहे हैं । मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बताता हूं, मैंने प्रश्न किया कि क्या सरकार मध्य प्रदेश में प्राय: सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बनाई गई योजना से संतुष्ट हैं ? हमारे मंत्री महोदय न यह जवाब दिया है कि इस तरह कुल मिला कर कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक रहा है । उधर अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश के लिये मूल पांचवीं योजना हेतु 24.80 करोड़ रुपये के कार्यक्रम परिव्यय की परिकल्पना की ग थी । और अभी जनवरी, 1978 के अन्त तक . . . .

MR. SPEAKER : Do not read out the whole thing. Put your question.

श्री सुखेन्द्र सिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि इससे कैसे संतुष्टी है ? और इस समस्या को कितना महत्व दिया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय केवल चरागाह बना देने से काम नहीं चलेगा । मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं जहां प्रति वर्ष सूखा पड़ता है । तो क्या उस एरिया के लिये कोई निश्चित

सिंचाई योजना लिफ्ट इरीगेशन या ट्यूब वैल की है ? मैंने पूछा था क्या आपके पास छठी पंचवर्षीय योजना के लिये कोई योजना है ? आपने कोई इसका जवाब नहीं दिया । यह राष्ट्रीय प्रश्न है, प्रति वर्ष करोड़ों रु० सरकार खर्च करती है । तो क्या आप आवश्यक नहीं समझते कि वहां के लिये कोई निश्चित सिंचाई योजना ट्यूब वैल, लिफ्ट इरीगेशन की सोचे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह 24 करोड़ रु० व्यय किये जाने का जो लक्ष्य था यह 5 वर्षों का था, उसमें से एक वर्ष तो छोड़ दिया गया । यह जो चौथा वर्ष अभी तक चला है उसमें भी सिर्फ दिसम्बर तक का शायद हिसाब है । पिछले दो महीने अभी बाकी हैं। प्राय: यह होता है कि खर्च पहले हो जाता हैं और उसकी अकाउन्टिंग आखिरी दो महीनों में होती हैं इसलिये व्यय कुछ कम जरूर दिखाई देता है । लेकिन वास्तव में पिछले वर्ष 1977–78 में जो धनराशि रखी गई थी वह प्राय: पूरी की पूरी व्यय हुई है । इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि सिंचाई का कार्यक्रम विशेष रूप से लिया गया था । जो यह धनराशि 24 करोड़ की थी उसमें से करीब दो तिहाई हिस्सा केवल सिंचाई के लिये था और उसका यूटिलाइजेशन ठीक हुआ है क्योंकि 13 करोड़ 46 लाख का अलौटमेंट था उसमें से 11 करोड़ 32 लाख का यूटिलाइजेशन सिर्फ दिसम्बर के अन्त तक हो गया है । तो इस प्रकार से इरीगेशन की ओर विशेष ध्यान है । अब रहा कि समस्यायें इस देश में बहुत हैं और उन सब को एक साथ नहीं सुलझाया जा सकता है । हमारा प्रयत्न यह जरूर है कि हम अधिक से अधिक समस्याओं को सुलझायें साथ ही मैं इतना और मानने के लिये तैयार हूं कि पिछले सालों में जिस गति से और जिस लगन के साथ काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और हम उस इम्प्रूवमेंट को लाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री राम सेवक हजारी : अध्यक्ष जी, हमारा कृषि प्रधान देश है और यह समस्या किसी एक प्रान्त की नहीं है बल्कि हर प्रान्त में हर वर्ष कहीं न कहीं हो जाती है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अगले दो, तीन सालों के अन्दर कोई ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहते हैं जिससे सिंचाई की समस्या हल हो जाये और अगले 2, 3, 4 सालों में सिंचाई समस्या का समाधान हो जाये ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी योजना के अनुसार अगले पांच सालों में 17 मिलियन हैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था की जाने वाली है । हमारी उत्सुकता इस बात से आंकी जा सकती है कि कितना बल दे रहे हैं सिंचाई कार्यक्रम पर । पिछले 25 वर्ष में केवल 23, 24 मिलियन हैक्टर भूमि की सिंचाई हुई है, जब कि हम अगले पांच सालों में 17 मिलियन हैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या मंत्री महोदय सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलायेंगे और कोई ऐसी सुनिश्चित योजना बनायेंगे कि वर्षानुवर्ष क्रम में अमुक क्षेत्र में इतनी सिंचाई की भूमि को अपनी लपेट में ले सकेंगे ? क्या इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर इस सदन को अवगत करायेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रश्न केवल मध्य प्रदेश के लिये हैं, परन्तु यदि हिदायत होगी तो इससे सदन को अवगत कराया जा सकता है

SHRI DWARIKADAS PATEL: May I know from the hon. Minister whether the Government is continuing the DPAP scheme in the Sixth Plan or not? Is there any change proposed in this scheme?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, a number of programmes which had almost the same content are proposed to be merged into one kind of programme. The DPAP, the Small Farmers' Programme and the Command Area Development, all these may be merged into one and at least in 2000 blocks intensive work will be taken up mainly with a view to provide full employment in those blocks.

दिल्ली में निर्माणों का गिराया जाना

*557. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य पुलिस दस्तों द्वारा विगत 3 मार्च को यमुना पार की खुरेजी और पालम आदि अनेक कालोनियों के अवैध निर्माण को जबरदस्ती उखाड़ फेंका गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी झोंपड़ियां उखाड़ी गयी हैं तथा उन उजाड़े हुए लोगों को कहां और कैसे बसाया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्तिऔर पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) । (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि खुरेजी के निकट शास्त्री नगर में छः स्थानों पर 3-3-1978 को मकान गिराये गये ।

(ख) झोंपड़ियां नहीं गिराई गई । दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों को गिराया गया । ऐसे मामलों में कोई वैकल्पिक वास नहीं दिया जाता ।

श्री विनायक प्रसाद यादव: 2 साल पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी को भी दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिये दिल्ली में झोंपड़ियां उजाड़ने की सनक सवार हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि शास्त्री नगर में जिन 6 जगहों पर मकान गिराये गये, वहां कुल कितने मकान गिराये गये ? मकान गिराने के लिये कितने बुलडोजर और कितने सी० आर० पी० के जवान वहां लगाये गये ? इसकी प्रीवियस सेंक्शन ली गई थी या नहीं ? यदि नहीं ली गई थी तो इन मकानों को बनने क्यों दिया गया, जो आज गिराने की जरूरत पड़ी ? मैं मंत्री जी से इन सवालों का जवाब चाहता हूं ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : इन 6 जगहों में से 4 जगहों पर तामीर जारी थी । दो जगहों पर जहां तामीर जारी नजर नहीं आती थी, लेकिन वहां सामान पड़ा हुआ था । इसलिए यह समझा जाता था कि छहों जगहों पर तामीर जारी है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : तामीर हम नहीं समझ रहे हैं ।

श्री सिकन्दर बख्त : तामीर यानी निर्माण जारी है । झोंपड़ियों का सवाल नहीं है । सी० आर० पी० ने डिमालीशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, यह सिर्फ म्युनिसिपल कार्पोरेशन के स्टाफ ने किया है । उसकी तारीखें मैं अर्ज कर देता हूं ।

पटपड़गंज रोड पर जहां कोई मजदूर और राज काम नहीं कर रहे थे, वहां ब्रिक्स और मोर्टार पड़ा हुआ था । उनको 27-12-77 को शो-काज नोटिस दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं आया । उसके बाद 2-1-78 को डिमालीशन नोटिस दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया । इसके बाद